भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2703
बुधवार, 11 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

बढ़ते तापमान का स्वास्थ्य पर प्रभाव

†2703. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष हो सकता है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अत्यधिक गर्मी के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों, विशेषकर इससे अधिक प्रभावित होने वाली आबादी पर पड़ने वाले प्रभावों से, निपटने के लिए क्या उपाय किए गए है;
(ग) क्या सरकार बढ़ते तापमान की समस्या से निपटने के लिए जलवायु सहायता और अनुकूलन संबंधी कार्यनीतियो को सुदृढ़ कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) - (ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने देश भर के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के साथ समन्वय करके निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे लू सहित चरम मौसम की घटनाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिली है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. ऋतुनिष्ठ और मासिक पूर्वानुमान जारी करना, उसके बाद तापमान और लू की स्थिति के विस्तारित-अवधि पूर्वानुमान जारी करना। समय पर सार्वजनिक पहुंच के लिए विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से भी पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान जानकारी प्रसारित की जाती है।

ii. राज्य सरकार के अधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों की योजना बनाने में मदद करने के लिए भारत भर में जिलावार लू भेद्यता एटलस।

iii. भारत भर में गर्म मौसम के संकट का विश्लेषण मानचित्र जिसमें दैनिक तापमान, पवनें और आर्द्रता की स्थिति शामिल है

iv. लू की स्थिति से ग्रस्त 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान (HAP) को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से संयुक्त रूप से लागू किया गया है।

ग्रीष्म ऋतु के शुरू होने से काफी पहले राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लू की तैयारी संबंधी बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है, तथा पूरे मौसम के दौरान समय-समय पर नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

(ग)-(घ) जी हां। आने वाले वर्षों में लू के कारणों को कम करने के लिए राज्यों की मदद से भारत सरकार द्वारा अनेक पहलें की गई हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCC) इस दिशा में प्रमुख पहलों में से एक है। इसके अतिरिक्त, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत विकास के लिए कम कार्बन वाली रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार सक्रिय रूप से उनका अनुसरण कर रहा है।

देश भर के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के साथ समन्वय में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है, जिससे चरम मौसम की घटनाओं, जिसमें लू भी शामिल हैं, के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिली है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से लू की स्थिति से प्रभावित 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान (HAP) को संयुक्त रूप से लागू किया गया।

*****